

न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर
समक्ष

एम०के०सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1336-एक/2012 - विरुद्ध आदेश
दिनांक 13-04-2012 - पारित द्वारा - अपर आयुक्त, चंबल
संभाग मुरैना - प्रकरण क्रमांक 08/2011-12 निगरानी

1- रोमेश सिंह 2- तेज सिंह
दोनो नावालिक पुत्रगण रामनरेश सिंह
सरपरस्त माता रानीदेवी ग्राम बसंतपुरा
तहसील रौन जिला भिण्ड

---आवेदक

- विरुद्ध
- 1- श्रीमती रेखा पत्नि स्व.किशन सिंह
ग्राम गुलाब नगर तहसील मल्लावा
जिला हरदोई उत्तर प्रदेश
 - 2- पुनू सिंह पुत्र सिरावन सिंह ग्राम
बसंतपुरा तहसील रौन जिला भिण्ड
 - 3- रामनरेश पुत्र पुनूसिंह ग्राम बसंतपुरा
तहसील रौन जिला भिण्ड
 - 4- श्रीमती मुन्नीदेवी पुत्री पुनूसिंह पत्नि नरसिंह
ग्राम बारहेट तहसील मिहोना जिला भिण्ड
 - 5- श्रीमती मुलादेवी पुत्री पुनूसिंह पत्नि प्रहलादसिंह
ग्राम रोहनी तहसील लहार जिला भिण्ड
 - 6- श्रीमती हीरुदेवी पुत्री पुनूसिंह पत्नि दिनेशसिंह
ग्राम जम्हौरा तहसील अटेर जिला भिंड

---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री आर०एस०सेंगर)
(अनावेदक-1 के अभिभाषक श्री एस.एन.श्रीवास्तव)
(अनावेदक-2 से 6 के अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा)
(अनावेदक-3 सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

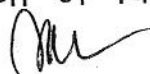
(आज दिनांक 11 - 1 - 2012 को पारित)

for यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना द्वारा
प्रकरण क्रमांक 8/2011-12 निगरानी में पारित आदेश दि.
13-4-2012 के विरुद्ध म०प्र०भू राजस्व संहिता, 1959 की
धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।



2/ प्रकरण का सारौंश यह है कि अनावेदक क्रमांक-2 पुनूसिंह ने तहसीलदार रोम को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर मौजा रओ, मौजा बसंतपुरा की शामिलालती भूमि के बटवारा किये जाने की मांग की। तहसीलदार रोम ने प्र. क. 5/2008-09 अ 27 पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 24-2-2009 से बटवारा स्वीकार किया। इस आदेश के विरुद्ध महिला रेखा देवी ने अनुविभागीय अधिकारी लहार के समक्ष अपील क्रमांक 257/09-10 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 30.10.2010 से अपील स्वीकार की गई एवं प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। इस आदेश के विरुद्ध अपर कलेक्टर, भिण्ड के समक्ष निगरानी क्रमांक 11/2010-11 प्रस्तुत हुई, जिसमें सुनवाई प्रारंभ की गई, सुनवाई के दौरान आवेदकगण की ओर से म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसकी प्रति अंतरिम आदेश दिनांक 30.11.2011 से अनावेदक/रिस्पा. को दी जाकर उत्तर हेतु प्रकरण लगाया गया। इसी अंतरिम आदेश के विरुद्ध पुनू सिंह एवं अन्य ने अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना के समक्ष निगरानी क्रमांक 8/11-12 प्रस्तुत कर दी। सुनवाई के दौरान निगरानीकर्तागण ने 17-2-12 को आवेदन देकर बताया कि म0प्र0शासन द्वारा 30-12-2011 को भू राजस्व संहिता में संशोधन किया गया है जिसके अनुसार निगरानी सुनने की अधिकारिता न्यायालय को नहीं है, इसलिये सक्षम न्यायालय में निगरानी सुनने हेतु वापिस की जाय। तदपरांत दूसरा आवेदन 16-3-12 को प्रस्तुत कर बताया कि आवेदकगण निगरानी में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं चाहते

for



हैं। अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण 8/2011-12 निगरानी में पारित आदेश दि. 13-4-2012 से आवेदन स्वीकार कर निगरानी समाप्त कर दी। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाए गए बिन्दुओं पर हितबद्ध पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।


4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक क्रमांक-2 पुनूसिंह ने तहसीलदार रोम को संहिता 1959 की धारा 178 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर मौजा रओ, मौजा बसंतपुरा की शामिलाली भूमि के बटवारा किये जाने की मांग की थी जिसे तहसीलदार रोम ने प्र. क. 5/2008-09 अ 27 में पारित आदेश दिनांक 24-2-2009 से बटवारा स्वीकार किया। इस आदेश के विरुद्ध महिला रेखा देवी ने अनुविभागीय अधिकारी लहार के समक्ष अपील क्रमांक 257/09-10 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 30.10.2010 से अपील स्वीकार की एवं प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। इस आदेश के विरुद्ध अपर कलेक्टर भिण्ड के समक्ष एवं अपर आयुक्त, चंबल संभाग के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई है एवं अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 13-4-2012 निगरानी निरस्त की है जिसके कारण अपर कलेक्टर, भिण्ड का आदेश दिनांक 30.11.2011 यथावत् हुआ है जबकि अपर कलेक्टर भिण्ड के न्यायालय में निगरानी का अंतिम रूप से निराकरण होना शेष है। मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 42 सन् 2011 द्वारा (30.12.2011) से प्रतिस्थापित कर

for



नियम बने हैं कि जो निगरानी उक्तावधि के पूर्व जिन न्यायालयों में प्रचलित रही है उनका निराकरण उन्हीं न्यायालयों में पूर्व की भाँति किया जावेगा अर्थात् अपर कलेक्टर के यहाँ निगरानी प्रकरण का अंतिम विनिश्चय होना है तथा उभय पक्ष को अपना-अपना पक्ष अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करने का उपचार प्राप्त है जिसके कारण अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 13-4-2012 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन जाने से निरस्त की जाती है एवं अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 8/2011-12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13-4-2012 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।


(एम०के०सिंह)
सदस्य

राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर

for